सम्पादक के नाम

इंडियन एक्सप्रेस और टेलीग्राफ का फर्क

जनसत्ता का नारा था, "सबकी खबर ले, सबको खबर दे"। खबर लेने के मामले में हम किसी को नहीं छोड़ते। जनसत्ता के बारे में लोग चाहे जो कहें मैं जानता हूं कि किसी खबर के लिए मैंने किसी से नहीं पूछा। ना कभी कुछ कहा गया ना पूछा गया। सिर्फ एक खबर पर प्रभाष जी ने कहा था कि चिकोटी नहीं काटते। खबर है तो बढ़िया से छापो। कल सुरेन्द्र किशोर की एक पोस्ट पर मैंने लिखा था, एक्सप्रेस की ओर से बोफर्स अभियान तो अरुण शौरी और गुरुमूर्ति ने ही चलाया था। और आज इंडियन एक्सप्रेस ने मौका दे दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पोर्टब्लेयर में थे। वहां उन्होंने सेल्यूलर जेल में हिन्दुत्व विचारक वीर सावरकर को जिस सेल में रखा गया था वहां बैठकर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। एक फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसे टेलीग्राफ ने निम्न विवरण के साथ पहले पन्ने पर छापा है।

अगर आपके विचार खुद प्रधानमंत्री की तरह ही देशभक्तिपूर्ण हैं तो आप सही हैं. नरेन्द्र मोदी ने इतवार की सुबह इस विवरण के साथ पोर्टब्लेयर से यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट की है "खुबसूरत पोर्ट ब्लेयर में में एक सुबह सूर्योदय जल्दी हुआ और परंपरागत परिधान."

इसके बाद पता चला कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था "हमारी आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले स्वतंत्रता संघर्ष के महान वीरों के बारे में सोच रहा हूं."

सेल्यूलर जेल में मोदी ने हिन्दुत्व विचारक वीर सावरकर को जिस सेल में रखा गया था वहां बैठकर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। 1913 में सावरकर ने एक अपील में लिखा था ".. इसलिए अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेज़ी सरकार के प्रति वफ़ादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है." दूसरी फोटो पीटीआई की है जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें वीर सावरकर के नाम से मशहूर वीडी या विनायक दामोदर सावरकर के बारे में यह नहीं बताया गया है कि वे स्वतंत्रता आंदोलन से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए थे। यह कथित इतिहास बदलने की फूहड़ कोशिशों में साथ देना नहीं तो और क्या है?

- साइबर नजर

भ्रष्टाचार के चलते मजाक बन गया है शासन

अनिल जन विजय

मोदी के सत्ताकाल में हुए 400 करोड़ के घोटाले पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी- जिस दिन पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में अपने भाषण में ये कह रहे थे कि चोरों को चौकीदार से डर लगने लगा है लेकिन चौकीदार सोएगा नहीं। और सभी भ्रष्टाचारियों को सजा दिला कर रहेगा। उसी दिन यानी 27 दिसंबर को उनके गृह राज्य और उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में उनके ही मंत्रिमंडल के दो सदस्यों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर गुजरात हाईकोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते शासन अब एक मजाक बन कर रह गया है।

मामला 400 करोड़ रुपये के फिशरी घोटाले का है। जिसमें मोदी के मंत्रिमंडल में रहे दो सदस्यों पुरुषोत्तम सोलंकी और दिलीप संघानी सीधे फंसे हुए हैं। दोनों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की।

जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने कहा कि "खुद को हंसी का पात्र बनाते हुए अगर आज शासन एक मजाक का मामला बन गया है और खुद को एक दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर लिया है। और अगर व्यवस्था के प्रति पागलपन आज का नियम हो गया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शायद भ्रष्टाचार को जाती है। विकास शायद भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शिकार बना है और उसके बुरे प्रभावों का उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है...."

".....भारत जैसे विकासशील देश में भ्रष्टाचार की समस्या सबसे ज्यादा गहरी है जहां इस खलनायक ने लोगों की जिंदगी से विकास को अगवा कर लिया है।"

हालांकि कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गयी 200 पेज की जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर मामले को सही पाया और उसने प्रथम दृष्ट्या उसे आगे बढ़ाने की बात कही। और इस कड़ी में न केवल मौजूदा फिशरी राज्य मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी बल्कि पूर्व कृषि मंत्री दिलीप संघानी के खिलाफ भी मुकदमा चलाए जाने पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रखने का हर वजह मौजूद है लिहाजा ट्रायल जारी रहना चाहिए।

समाज पर पड़ने वाले भ्रष्टाचार के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस पर्दीवाला ने आगे कहा कि "अगर किसी से किसी अकेले कारक के बारे में पूछा जाए जिसने हमारे समाज की समृद्धि और प्रगति को बुरी तरीके से रोके रखा है तो उसका जवाब बगैर किसी ना-नुकुर के भ्रष्टाचार है। अगर एक विकासशील देश में समाज कानून और व्यवस्था के हत्यारों से भी बड़े किसी राक्षस का सामना कर रहा है तो वो सरकार और राजनीतिक दलों के ऊपर बैठे हुए भ्रष्ट तत्व हैं।"

कोर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि अगर एक राज्य के मौजूदा मंत्री पर मुकदमा चलाया जाता है तो सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही उसने इस बात को स्वीकार करने से भी इंकार कर दिया कि शिकायत किसी गलत इरादे से की गयी है।

कोर्ट ने कहा कि एकबारगी अगर ये मान भी लिया जाए कि शिकायत गलत इरादे से की गयी है तो भी इसे शिकायत को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अगर शिकायत में कोई गंभीर आरोप है तो उसको जुटाए गए सबूतों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि आपराधिक न्यायिक प्रणाली मुकदमों के जल्द निपटारे की वकालत करती है। साथ ही विधायिका भी मामलों को जल्द से जल्द खत्म करने के पक्ष रहती है। ऐसे में ऊपरी कोर्टों को निचली अदालतों के मामलों में कम से कम दखल देने की जरूरत है। इसके साथ ही दोनों की याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया।

अंत में आइन रैंड्स एटलस को कोट करते हुए जस्टिस पर्दीवाला ने कहा कि "जब आप देखते हैं कि कामकाज सहमति से नहीं बल्कि दबाव में हो रहा है- जब आप देखते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में आपको उन लोगों से इजाजत लेने की जरूरत है जो कुछ नहीं पैदा करते हैं- पैसा उनकी ओर बह रहा है जो अच्छे के पक्ष काम नहीं करते बल्कि पक्षपात करते हैं- जब आप देखते हैं कि इंसान काम की बजाय भ्रष्टाचार से समृद्ध हो रहा है और आप का कानून उनके खिलाफ आप की रक्षा नहीं करता है बल्कि आपके खिलाफ उनकी रक्षा करता है- जब आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार को पुरस्कृत किया जा रहा है और ईमानदारी आत्म बलिदान साबित हो रही है- तब आप समझ सकते हैं कि आपका समाज गर्त की ओर जा रहा है।"

जज की ये पूरी टिप्पणी उस दौर के भ्रष्टाचार को लेकर की गयी है जिसे मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में अंजाम दिया गया था। 400 करोड़ रुपये के इस घोटाले का मामला निचली अदालत में चल रहा है। और इसमें सबसे खास बात ये है कि उस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने की बात तो दूर उसी विभाग का मंत्री बनाए रखा गया है। लेकिन इस पर न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करने वाले हमारे पीएम का कोई ध्यान गया।

और न ही वो इसकी जरूरत समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। या फिर कोर्ट के इस फैसले और टिप्पणी के बारे में उनको पता नहीं होगा। लेकिन चूंकि मुख्यधारा का मीडिया इसे उठाने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा प्रधानमंत्री जी को भी इस पर बोलने और कार्रवाई करने की क्या जरूरत है। इसी तरह के न जाने कितने घोटाले गुजरात में तैर रहे हैं जिसकी न तो किसी ने सुध ली और न ही देश में उस पर बात हुई।

अब जब कि चौकीदार एक ब्रांड बन गया है। तब राफेल जैसे महाघोटाले को भी हवा में उड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट की लीपापोती का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और मामला है कि आगे ही बढ़ता जा रहा है। और आखिर में जनता के बीच भी इस तरह की एक अवधारणा बन रही है जिसका जवाब देना पीएम मोदी समेत उनकी पूरी सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। अनायास नहीं चौकीदार के चोर होने के नये ब्रांड की मांग बढ़ गयी है। और विपक्ष तो विपक्ष शिवसेना जैसे गठबंधन के सहयोगी भी इसके खरीदार बन गए हैं।

आप इस मोदी घोटाले के बारे मे जानकर हैरान हो जाएँगे

गिरीश मालवीय

आप 2G घोटाले को भूल जाएंगे। कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलब्लॉक घोटाला भी इसके सामने बहुत छोटा है, यहां तक कि रॉफेल घोटाला भी आपके आपके जीवन को इतना प्रभावित नही करेगा। यह है स्मार्ट मीटर घोटाला....

आप सभी ने वर्षों पहले अपने घरों में लगे बिजली के पुराने मीटर देखे होंगे जिसमें एक लोहे की प्लेट लगी रहती थी, वह प्लेट घूमती ओर उसी की रीडिंग के अनुसार आपका बिजली बिल निर्धारित किया जाता था। जमाना बदला और उसके बाद उन मीटरों का स्थान डिजिटल/ इलेक्ट्रॉनिक मीटर ने लिया जिसे लगाए भी आपको ज्यादा समय नही हुआ होगा लेकिन अब इसे फिर एक बार बदला जा रहा है। अब मोदी सरकार आने वाले तीन सालो में देशभर में बिजली के सभी मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड में बदलने जा रही है। देश भर में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।

अब बिजली के बिल भरने की बात ही नही है क्योंकि अब यह व्यवस्था प्रीपेड कर दी गयी हैं यानी यदि आपकी जेब मे पैसा है तो पहले रिचार्ज करवाइये उसके बाद ही आपके घर मे 'बिजली देवी' का प्रवेश होगा। इसे अच्छे शब्दों में बिजली मंत्रालय ने इस तरह बताया है 'स्मार्ट मीटर गरीबों के हित में है। उन्हें पूरे माह का बिल एक बार में चुकाने की जरूरत नहीं होगी। वे जरूरत के मुताबिक बिल चुका सकेंगे'।

इस मीटर की सारी गतिविधियां एक मोबाइल एप के जरिए आपके फोन पर अपडेट होंती रहेगी। सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब आप यह नही बोल सकते कि मेरे घर मे 2 ही पँखे 4 ट्यूबलाइट ओर 1 फ्रिज ही है..... एप पर आपको ओर बिजली विभाग को सब दिख जाएगा कि कितने उपकरण आपके यहाँ काम कर रहे हैं इस व्यवस्था में लोड ज्यादा होने पर सेंट्रल कार्यालय से उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। इसमें एक सीमा के बाद मीटर में लोड जा ही नहीं पाएगा।

सभी स्मार्ट मीटर को बिजली निगम में बने कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। कर्मचारी स्काडा सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल रूम से ही मीटर रीडिंग नोट कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर कोई मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका संकेत कंट्रोल रूम में मिलेगा। अगर कोई उपभोक्ता समय पर बिजली बिल नहीं भरता, तो कंट्रोल रूम से ही उसका मीटर कनेक्शन भी काटा जा सकेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं के घर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

चलिए यह समझिए कि यह घोटाला कैसे है? दरअसल यह दावा किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर को लगाने की एवज में उपभोक्ताओं से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, उपभोक्ता का पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर फ्री में लगाया जा रहा है। साथ ही पांच साल तक मीटर में कोई गड़बड़ी होती है तो भी मीटर बिना किसी शुल्क के बदला जाएगा।

वैसे सच तो यह है कि कोई चीज फ्री में नही लगाई जाती, फ्री में लगाने से पहले ही सारा केलकुलेशन बैठा लिया गया है कि पहले 6 महीने में ही आपका जो बिल बढ़ा हुआ आएगा उसी में यह राशि समायोजित कर दी जाएगी, ओर जिन घरों में यह मीटर लगाए गए हैं उन सभी घरों में जो बिल आए हैं उसमें सवा से डेढ़ गुनी अधिक खपत दिखाई दे रही है।

वैसे सच तो यह है कि कोई चीज फ्री में नही लगाई जाती, फ्री में लगाने से पहले ही सारा केलकुलेशन बैठा लिया गया है कि पहले 6 महीने में ही आपका जो बिल बढ़ा हुआ आएगा उसी में यह राशि समायोजित कर दी जाएगी, ओर जिन घरों में यह मीटर लगाए गए हैं उन सभी घरों में जो बिल आए हैं उसमें सवा से डेढ़ गुनी अधिक खपत दिखाई दे रही है।

खुले बाजार में फिलहाल सबसे सस्ता सिंगल फेज प्रीपेड बिजली मीटर अभी 8 हजार रुपये का मिल रहा है। हालांकि अच्छी गुणवत्ता वाला मीटर खरीदने के लिए लोगों को 25 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। अब ये कम्पनी जो स्मार्ट मीटर लगा रही हैं उसमें किस तरह से आपसे पैसा वसूला जाएगा आप खुद ही सोच लीजिए।

दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार यह मीटर सप्लाई कौन कर रहा है? कही न कही तो इनका उत्पादन किया जा रहा होगा? क्या विद्युत नियामक आयोग स्वतंत्र रूप से इन स्मार्ट मीटरों की जाँच करवा चुका है? क्योंकि सारा झोलझाल तो यही है देश भर में इन स्मार्ट मीटर की आपूर्ति एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल कर रहा है। दरअसल विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी लिमिटेड, पीएफसी, आरईसी और पावरग्रिड के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम बनाया है जिसे ईईएसएल कहा जाता है।

अब यही असली घोटाला है। दरअसल यह कंपनी भारत सरकार ने 2009 में बनाई थी लेकिन इस कंपनी ने 2014 तक कोई काम नहीं किया। यह कंपनी सिर्फ कागज तक ही सीमित रही। जून 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने अचानक इस कंपनी को देश के 100 शहरों में एलईडी बल्ब लगाने का काम दे दिया जिसे आप उजाला योजना के नाम से जानते हैं।

इस कंपनी में कोई क्षमता ही नहीं थी कि उसे इतना बड़ा काम दिया जाए, क्योंकि कंपनी के पास कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। यह कंपनी न तो एलईडी का उत्पादन करती थी और न ही उसके पास एलईडी बल्ब लगवाने का कोई साधन था। वह सिर्फ दूसरी छोटी कंपनियों को सब-कांट्रेक्ट देकर चीन से एलईडी बल्ब खरीदवा रही थी और लगवा रही थी।

ओर किसी ने नही बीजेपी की सहयोगी शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में कार्यकारी संपादक संजय राउत ने 2016 में 'सच्चाई' नामक शीर्षक के तहत एलईडी बल्ब में भारी घोटाले का पर्दाफाश किया था।

जो बल्ब देश भर में तीन सालो के लिए लगवाए गए थे वह कुछ महीनों बाद ही खराब होना शुरू हो गए। जब उपभोक्ता इन्हें बदलने के लिए पुहंचे तो इन्हें बेचने वाले नदारद थे। सभी जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी हैं बहुत विवाद भी हुए लेकिन इस कम्पनी पर कुछ भी कार्यवाही नही हुई। इस EESL कंपनी को देश भर में स्ट्रीट लाइट को LED से बदलने का ठेका भी दिया गया जिसके सब कांट्रेक्ट उन्होंने ऐसे लोगो को दिए जो एक साल में ही शहर छोड़ कर भाग गए .....आप स्थानीय अखबारों में इनके किस्से पढ़ सकते हैं, जो सैकड़ों की संख्या में छपे है और यह कम्पनी सिर्फ द्यदस्र बल्ब तक ही सीमित नही है। लाखो पंखे इन्होंने खरीदे हैं और यहाँ तक कि डेढ़ टन के AC भी हजारों की संख्या में इन्होंने खरीदे है लेकिन कही भी देखने मे नही आए आफ्टर सेल्स सर्विस की कोई व्यवस्था इस कम्पनी के पास नही है क्योंकि यह कम्पनी किसी तरह का उत्पादन नही करती।

अब एक बार फिर ऐसी कम्पनी को आगे करके मनमाने दामो पर स्मार्ट मीटर की खरीदी करवाई जा रही है किससे यह मीटर खरीदे जा रहा है उनकी गुणवत्ता को कैसे निर्धारित किया गया है इसका कुछ अता पता नही है। दरअसल यह पूरी योजना गरीब आदमी के हितों के नाम पर बड़ी पावर कंपनियों को लाभ में लाने की योजना है जिसमे बड़े पैमाने पर अडानी टाटा ओर रिलायंस जैसे उद्योगपतियों ने निवेश कर रखा है। खुद बिजली मंत्रालय ने माना है कि सभी मीटर को प्री-पेड कर देने से बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की लागत काफी कम हो जाएगी और डिस्कॉम आसानी से घाटे से उबर जाएंगी। अभी देश के कई राज्यों की डिस्कॉम भारी घाटे में चल रही है।

सारे स्मार्ट मीटर चाइना से बेभाव में खरीदे जाएंगे जो बिना गुणवत्ता जांचे गए यह मीटर आपके घर की विद्युत खपत को सीधे डेढ़ गुना करके बताएंगे ओर आपसे उसका पैसा प्रीपेड के नाम पर पहले ही वसूल किया जाएगा। आपकी शिकायत को अमान्य करके कहा जाएगा कि अब तक आप चोरी कर रहे थे ..... यही है मोदी सरकार की सौभाग्य योजना।